ल.अं./51/एसएलबीसी/जून 2025/ 484

15.10.2025

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय : राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2025 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 24.09.2025 का कार्यवृत्त

कृपया दिनांक **24.09.2025** को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2025 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही बिन्दु आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(शैलेंद्र कुमार सिंह)
महाप्रबंधक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2025 तिमाही की बैठक
दिनांक 24.09.2025 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2025 त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 24.09.2025 को **"महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ** में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में डॉ0 सारिका मोहन, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र. शासन; श्री सुशील कुमार सिंह, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री अमित सिंह बंसल, आई.ए.एस., विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन; श्री समीर, आई.ए.एस., विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन; श्री इंद्रजीत सिंह, आई.ए.एस., निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण; श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री राजीव कुमार, महाप्रबंधक, सिडबी, लखनऊ; श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गई। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 21.05.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

मार्च 2025 त्रैमास की बैठक दिनांक 21.05.2025 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./51/एस.एल.बी.सी./मार्च 2025/140 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

बैठक के प्रारम्भ में **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)** ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में गठित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों से सभा को निम्नवत अवगत कराया:

- माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद लखनऊ में दिनांक 27.06.2025 को MSME Day एवं दिनांक 30.07.2025 से 01.08.2025 तक "CM Yuva Conclave" का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों को चेक के माध्यम से ऋण वितरण करने के साथ साथ CM Yuva Yojana के लाभार्थियों द्वारा स्टाल लगाए गए।
- दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक के लिए 3 माह हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक संतृप्तीकरण अभियान की शुरूआत की गई है जिसमें प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों मे कम से कम एक शिविर का आयोजन करते हुए आमजनमानस को वित्तीय समावेशन योजनाओं से लाभान्वित करना, Re KYC, Cyber Security Threats, Awareness about Money Mule Accounts एवं Nominee Add किया जाना इत्यादि शामिल है।
- विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर दिनांक 17.09.2025 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा एमएसएमई योजना के लाभार्थी को चेक के माध्यम से ऋण वितरण किया गया।
- जनपद ग्रेटर नोयडा में दिनांक 25-29 सितंबर 2025 के मध्य यू पी इंटरनेशन ट्रेड शो का आयोजन किया जाना है। ट्रेड शो के दौरान दिनांक 26.09.2025 को माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में एक बैंकिंग सत्र का आयोजन किया जाना है जिसमें रू 3,500 करोड़ का ऋण वितरण कार्यक्रम में बैंक ऋण लाभार्थी को चेक वितरण के साथ-साथ साइबर सुरक्षा पर उपस्थित ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा।

❖ वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02.10.2025 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर दिनांक 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक स्वछता ही सेवा (SHS), 2025 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की थीम "स्वच्छोत्सव " है। अभियान के दौरान बैंकों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ दिनांक 25.09.2025 प्रातः 08:00 बजे राष्ट्रव्यापी श्रमदान गतिविधि "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" भी किया जाना है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सभी गतिविधियों मे बढ़-चढकर हिस्सा लें एवं दिनांक 25.09.2025 प्रातः 08:00 बजे "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" अपना श्रमदान भी दे।

❖ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2024 में नई दिल्ली में Cyber Fraud Mitigation Centre स्थापित किया गया है, जो साइबर वित्तीय अपराधों के विरुद्ध एक "वार रूम" के रूप में कार्य कर रहा है। साइबर क्राइम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कल्ली पश्चिम, लखनऊ में दिनांक 30.07.2025 को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 हेतु एक Standalone कॉल सेन्टर का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें CFMC भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) नागरिकों द्वारा दर्ज की गई वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने में मदद करता है ताकि पीड़ित के खाते से साइबर धोखेबाज के खाते में धन के प्रवाह को रोका जा सके और वास्तविक समय में ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा की जा सके।

❖ वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यो रू 6.45 लाख करोड़ के सापेक्ष कुल उपलब्धि रू 1.91 करोड़ (29.64%) रही है। एम.एस.एम.ई. एवं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष क्रमश: 36.08% एवं 22.57% की उपलब्धि दर्ज की गई है।

❖ प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2025 के स्तर 59.04 से बढ़कर जून 2025 में 59.40 पहुंच गया है। साथ ही 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या भी मार्च 2025 के स्तर 7 से घटकर जून 2025 मे 6 रह गई है।

❖ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु समस्त बैंकों को 1.50 लाख आवेदनों पर ऋण वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना की प्रगति की समीक्षा राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। बैंको से अनुरोध किया कि सभी शाखाओं को लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करें।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में **श्री लाल सिंह, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन करते हुए समिति को निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियो से अवगत कराया :

❖ दिनांक 2-3 सितंबर,2025 को माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने GST Council की बैठक में GST की दर कम करने की घोषणा की गयी। वस्तु एवं सेवा कर को सरल बनाने के ऐतिहासिक कदम के तहत GST संरचना को 4 दरों (5%,12%,18% & 28%) से घटाकर 2 मुख्य दरें 5% (Merit Rate) तथा 18% (Standard Rate) करने के साथ Luxury Goods हेतु 40% विशेष दर की गई है। GST दरों में संशोधन दिनांक 22.09.2025 से देशभर में प्रभावी हो गया है। GST दरों में कमी होने से बैंकिंग लेनदेन, ऋण, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के उपयोग, बैंक और NBFCs को रिटेल क्रेडिट, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि में वृद्धि होने की संभावना है। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर GST दर 0% होने से प्रीमियम सस्ते होंगे, बीमा का दायरा और ग्राहकों की भागीदारी बढ़ेगी। MSMEs और कृषि क्षेत्र में इनपुट लागत में कमी होगी, working capital की मांग बढ़ेगी जिससे बैंक ऋण और वित्त उपलब्धता बेहतर हो सकेगी।

❖ U.S. government ने भारत से आयातित कुछ उत्पादो पर tariff को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है जिसका प्रभाव भारत के निर्यातको पर पड़ेगा। निर्यात शुल्क बढ़ते हैं तो उत्पाद महंगे होते है तथा विदेश मे ग्राहक इसे खरीदने मे कम रुचि दिखाते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्यात बिक्री घटती है साथ ही बैंकों की ट्रेड फाइनेंसिंग सेवाएँ प्रभावित होंगी। इसके प्रभाव को देखते हुए बैंको द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिसमे मुख्य रूप से उद्योगों और MSME ईकाइयो को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक आय स्रोतों पर

ज़ोर देना, जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाना, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए पारदर्शिता बनाए रखना इत्यादि शामिल है।

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक देशभर की समस्त ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए 3 माह का Saturation Drive चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान हमारे प्रदेश की 57,702 ग्राम पंचायतों में शिविरों के दौरान आमजनमानस को वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ प्रदान करना, बैंक खातों में केवाईसी एवं नामिती अद्यतन करना एवं लोगों को Digital धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अद्यतन स्थिति के अनुसार अभी तक 54,000 (93%) से अधिक शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी.एम.स्वनिधि योजना के पुनर्गठन एवं समयावधि के विस्तार के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किए गए। संशोधित दिशा-निर्देशो के अनुसार योजनान्तर्गत प्रथम चरण हेतु ₹ 15,000/- द्वितीय चरण हेतु ₹ 25,000/- एवं तृतीय चरण हेतु ₹ 50,000/- तक का ऋण स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड ऐसे पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में उपलब्ध होगा, जिन्होंने अपने दूसरे ऋण की किशत सफलतापूर्वक चुका दी है और तीसरे ऋण के लिए पात्र हैं। यह कार्ड एक घरेलू कार्ड होगा और शुरुआत में क्रेडिट सीमा ₹10,000 होगी जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर ₹ 30,000 कर दिया जाएगा। यह कार्ड 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

- नोडल एजेंसी - सूडा द्वारा भी दिनांक 17.09.2025 से 02.10.2025 तक प्रदेश में 16 दिवसीय लोक कल्याण मेला आयोजित किया जाना है जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा प्रदान करना और उन्हे डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होने बैंको से आह्वाहन किया कि पूर्व की भांति इस बार भी योजना का लाभ अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचाने हेतु सहयोग प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 28.08.2025 के दौरान सभी प्रकार के Unclaimed Assets के settlement हेतु अक्तूबर माह में प्रत्येक जनपद मे जिलाधिकारी कार्यालय मे विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है। साथ ही शेष बचे Unclaimed Assets को दिसंबर 2025 तक settle किया जाना अपेक्षित है। उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक Unclaimed Deposit को इस समयावधि मे settle किया जा सके।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की जून तिमाही के अंत में प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय रु 30.92 लाख करोड़ पहुंच गया है।
- बैंकों ने कुल जमा एवं अग्रिम मे क्रमशः 10.60% एवं 9.47% की Y-o-Y Growth दर्ज की है।
- ऋण जमानुपात जून 2025 में 59.40% के स्तर पर पहुंच गया है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ऋण में क्रमशः 12.04%, 5.13% एवं 22.37% की Y-o-Y Growth दर्ज की है।
- वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यो के सापेक्ष 29.64% की उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही एमएसएमई, कृषि एवं अन्य क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः 36.08%, 22.57% और 11.72% की उपलब्धि दर्ज की गई है।
- सरकारी योजनाओं यथा **CM YUVA, ODOP, PM SVANidhi, PM SURYA Ghar, PM Vishwakarma, DAY NULM, R-SETI Credit Linkage, SHG Credit Linkage एवं CGTMSE** के अंतर्गत और सुधार किए जाने हेतु सभी बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों से अनुरोध किया।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होने सभा में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सार्थक चर्चा हेतु शुभकामनाएँ दी।

श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

- ❖ ऋण जमानुपात में तिमाही दर तिमाही बढ़ोत्तरी दर्ज करते हुए जून 2025 मे प्रदेश का ऋण जमानुपात 59.40% के स्तर पर पहुंच गया है जिसे 60% तक पहुंचाया जाना अभी शेष है। अग्रिम की अपेक्षा जमा में अधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। उन्होने जनपदवार अग्रिम की संभावनाओ को analysis कर ऋण वितरण बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया ताकि जनपद के साथ साथ प्रदेश के ऋण जमानुपात मे सुधार हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ प्रदेश में कार्यरत ग्रामीण शाखाओं को शाखाओ से संबद्ध ग्रामों की सूची को पुनः मैप कराकर उपलब्ध कराने हेतु जनपद के अग्रणी जिला प्रबन्धको को निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- ❖ वार्षिक ऋण योजना 2025- 26 के अंतर्गत प्रथम त्रैमास मे बैंको द्वारा सेक्टरवार बेहतर उपलब्धि दर्ज की है।

- ❖ भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 माह संतृप्तीकरण अभियान के दौरान बैंको, प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासो की सराहना करते हुए उन्होने जनधन एवं अन्य बैंक खातो में KYC अद्यतन किए जाने की प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश में KYC अद्यतन हेतु आवंटित कुल लक्ष्य 4.70 करोड़ खातों के सापेक्ष कुल 22 लाख खातो मे ही Re-KYC किया गया है। उन्होने बैंको से आहवाहन किया कि संतृप्तीकरण अभियान समाप्त होने के पश्चात भी शीघ्र अतिशीघ्र KYC due खातो मे Re-KYC किया जाना सुनिश्चित करें ताकि जनधन खाताधारको को बिना किसी बाधा के DBT का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होने बैंक मित्रो को भी केवाईसी अद्यतन किए जाने हेतु Incentivize करने हेतु आहवाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना के अनुसार जनपद स्तर पर त्रैमासिक आधार पर डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. बैठको का आयोजन किया जाता है। पिछले कुछ त्रैमासों में यह पाया गया है डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. बैठक की तिथि निर्धारित होने के बाद भी अंतिम समय में जिला प्रशासन द्वारा बैठक रद्द कर दी जाती है जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होने प्रदेश शासन से अनुरोध किया कि जनपद स्तरीय अधिकारियों को डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. की बैठक निर्धारित तिथि पर करवाने हेतु जागरूक करे एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. बैठको के अनसुलझे मामलो की प्रदेश स्तरीय बैठको मे चर्चा की जा सके।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, उ.प्र.)

- ❖ ULI एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, जो भुगतान में यूपीआई के समान है, जिसका उद्देश्य निर्बाध, सहमति-आधारित डेटा पहुंच और तेज डिजिटल ऋण प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई, कृषि और वंचित उधारकर्ताओं के लिए ऋण पहुंच को आसान बनाना है। ULI को बढ़ाने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने, मंत्रालयों और राज्यों को डेटासेट तक एपीआई-आधारित पहुंच प्रदान करने, और रिकॉर्डों को डिजिटल बनाने, उधारदाताओं को शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ❖ Unclaimed Deposit के settlement हेतु अक्तूबर माह में जनपद स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाना है। उन्होने बैंको से आहवाहन किया कि Unclaimed Deposit की पहचान कर ऐसे खातो के शीघ्र अतिशीघ्र settlement हेतु आवश्यक कार्यवाही करें साथ ही इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक Unclaimed Deposit को इस समयावधि मे settle किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री सुशील कुमार सिंह, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सर्वप्रथम गत तीन माह से चल रहे संतृप्तीकरण अभियान के दौरान प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंको, अग्रणी जिला प्रबन्धको एवं प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासो की सराहना करते हुए अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

❖ संतृप्तीकरण अभियान की समाप्ति में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे ग्राम पंचायत जहां आने वाले दिनो में कैंपो का आयोजन किया जाना है, में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधों द्वारा सहभागिता किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग)

❖ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रदेश में सबसे अधिक शाखा नेटवर्क के साथ कार्य कर रहा है। संतृप्तीकरण अभियान के दौरान कुल 57,702 ग्राम पंचायतों मे से 22,000 से अधिक ग्राम पंचायतों मे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा कैंप आयोजित किए जाने थे जिसके सापेक्ष बैंक द्वारा विभिन्न FI पैरामीटर के अंतर्गत प्रगति काफी कम दर्ज की गई है। उन्होने संबन्धित बैंक से अनुरोध किया कि अभियान के दौरान दर्ज प्रगति का आत्ममंथन करते हुए इसमे सुधार लाने हेतु आवश्यक प्रयास करें।

(कार्यवाही: उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक)

❖ अभियान के दौरान देशभर में सामाजिक सुरक्षा योजना यथा PMJJBY & PMSBY के अंतर्गत क्रमश: 81 लाख एवं 180 लाख नामांकन करने के साथ साथ अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 23 लाख लोगो को जोड़ा गया है जो निश्चय ही एक बेहतरीन उपलब्धि है। कैंपो के दौरान 9000 से अधिक लोगो के PMJJBY & PMSBY के अंतर्गत क्लेम का निस्तारण भी किया गया है जो 9000 परिवारों को उनके दु:ख के समय मे एक वित्तीय सहायता के रूप मे कार्य करेगा।

❖ गत वर्ष प्रदेश द्वारा कृषि ऋण के अंतर्गत कुल 83% की उपलब्धि दर्ज की गई जो देश के स्तर 110% से काफी कम है। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा कृषि ऋण के अंतर्गत प्रदेशवार लक्ष्यो का आवंटन किया जाता है। समस्त बैंको से आहवाहन किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कृषि ऋण के अंतर्गत प्रदान किए गए लक्ष्यो को शत प्रतिशत हासिल करना सुनिश्चित करें। प्रदेश में Allied Activity के क्षेत्र मे पर्याप्त संभावनाएं व्याप्त है जिसके अंतर्गत ऋण प्रदान किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

नाबार्ड के प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में आने वाली असुविधाओ की पहचान करते हुए उन्हे दूर करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाये ताकि प्रदेश कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर उपलब्धि दर्ज कर सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं नाबार्ड)

❖ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे जनपद जहां ऋण प्रदान करने की पर्याप्त संभावनाएं न होने के बावजूद अग्रिम के क्षेत्र मे बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, को विभेदक भार प्रणाली (Differential Weightage System) के अंतर्गत 125% का Weightage प्रदान किया जाता है। उन्होने ऐसे किसी एक जनपद में अध्ययन कराने के साथ साथ गत वर्षो मे जनपद के अग्रिम के विश्लेषण हेतु आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक)

❖ प्रदेश का ऋण जमानुपात मे गत वर्षो मे काफी अच्छी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है जिसके लिये समस्त बैंको को बधाई दी। साथ ही प्रदेश के ऋण जमानुपात के स्तर (59.40%) को देश के स्तर (70%) तक पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाते हुए प्रयास किए जाने हेतु आहवाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ केंद्र/ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओ के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रो के त्वरित निस्तारण, योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मिलने वाले विभिन्न लाभों यथा ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी सब्सिडि इत्यादि को निर्धारित समयावधि मे प्रदान करना, आवेदन पत्रों का 30 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि इससे संबन्धित प्राप्त होने शिकायतों में कमी लाने हेतु सभी बैंक विशेष प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

डॉ. सारिका मोहन, आई.ए.एस., महानिदेशिक, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित विभाग, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सभा को निम्न मुख्य बिन्दुओ से अवगत कराया :

- प्रदेश का ऋण जमानुपात मार्च 2025 के स्तर 59.04 में 0.36% की बढ़ोत्तरी दर्ज करते हुए जून 2025 में 59.40 पहुंच गया जिसके लिए समस्त बैंको को बधाई दी। ऐसे जनपद जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है, की संख्या घटकर 6 रह गई है। ऐसे जनपदों में उपलब्ध अवसरों की पहचान कर एक विशेष कार्ययोजना एवं मानिटरेबल एक्शन प्लान बनाते हुए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश के ऋण जमानुपात को 65% से 70% तक पहुंचाया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वार्षिक ऋण योजना 2025-26 मे जून 2025 में 29.64% की उपलब्धि दर्ज की गई है तथापि कृषि एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में अपार संभावनाएं व्याप्त है एवं बैंको द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- केंद्र/ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं यथा PMJJBY, PMSBY, CM Yuva Yojana, ODOP इत्यादि योजनाओ का व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- प्रदेश मे चल रहे संतृप्तीकरण अभियान के दौरान बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए सभी बैंकर्स को बधाई दी।
- SDG India Index 4.0 के अंतर्गत प्रदेश के इंडीकेटर प्रति लाख जनसंख्या पर शाखाओ की संख्या एवं प्रति लाख जनसंख्या पर ए.टी.एम. की संख्या राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है जिसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु बैंको द्वारा एक कार्ययोजना बनाते हुए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री इंद्रजीत सिंह, आई.ए.एस., निदेशक, यूपीनेडा, उत्तर प्रदेश ने अपने सम्बोधन में निम्नवत अवगत कराया :

- सर्वप्रथम उन्होने गत तीन माह – जुलाई, अगस्त एवं सितंबर मे प्रदेश में पी. एम. सूर्य घर योजना के अंतर्गत किए गए सोलर इन्स्टालेशन में प्रदेश के पैन इंडिया प्रथम स्थान होने पर समस्त बैंकर्स को बधाई दी जिसमे से जनपद वाराणसी में बैंको द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है।
- पी. एम. सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 24,000 से अधिक आवेदन पत्रो में ऋण वितरण किया जा चुका है। बैंको से आहवाहन किया कि संबन्धित वेडर्स से संपर्क कर सोलर इन्स्टालेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लें ताकि अग्रिम कार्यावाही पूर्ण की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- पी. एम. सूर्य घर योजना के अंतर्गत ऋण वितरण हेतु लंबित आवेदन पत्रो के त्वरित निस्तारण हेतु बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- ग्रामीण क्षेत्रो मे लगने वाले कैंपो मे योजना के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी योजना के प्रति जागरूक हो सके एवं योजना का लाभ भी प्राप्त कर सके।

श्री अमित कुमार बंसल, आई.ए.एस., विशेष सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सदन को निम्न बिन्दुओ से अवगत कराया :

- प्रदेश के ऋण जमानुपात में मार्च 2025 के स्तर से जून 2025 में वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार के अपेक्षानुसार इसे बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ प्रदेश में **"विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047"** अभियान की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत आमजनमानस से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से संबन्धित QR Code के माध्यम से सुझाव मांगे जा रहे है। बैंको से आहवाहन किया कि QR Code के माध्यम से दिये जाने वाले Feedback के प्रचार प्रसार हेतु बैंक शाखाओ में बैनर, पोस्टर के माध्यम से जागरूक करें तथा उन्हे विभिन्न सेक्टर के अंतर्गत Feedback प्रदान किए जाने हेतु प्रेरित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री समीर, आई.ए.एस., विशेष सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सभा को निम्नवत अवगत कराया :

❖ प्रदेश में कृषि क्षेत्र विशेषकर फ़सली ऋण के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे ऋण अन्य राज्यो की तुलना में काफी कम है जो चिंता का विषय है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण में कमी हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन कराये जाने की आवश्यकता है।

❖ प्रदेश का ऋण जमानुपात गत 2 वर्षों में 58% से 60% के मध्य रहा है जिसे बढ़ाने हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

❖ गत 3 वर्षों में 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदो की संख्या 9 से घटकर 6 हो गई। 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों के ऋण जमानुपात की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार की जाये।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक)

❖ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र मे बैंको द्वारा प्रदान किए जा रहे Fresh Loan & Repayment की सूचना पृथक पृथक रूप से शामिल की जाये ताकि प्रदेश मे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम की वास्तविक सूचना परिलक्षित हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ CM Yojana प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण वितरण किए जाने हेतु बैंको से आहवाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ वर्तमान मे tariff बढ़ने से Exporter पर प्रभाव पड़ने की आशंका है एवं इससे विभिन्न सेक्टर यथा Leather, Handicraft इत्यादि भी प्रभावित होंगे। जनपद नोयडा में आयोजित होने वाले इन्टरनेशनल ट्रेड शो में Exporters भी मौजूद होंगे। उन्होने इन सेक्टर के Exporters के लिए यदि कोई बैंक योजना हो तो इसे ट्रेड शो के दौरान प्रचारित किए जाने हेतु बैंको से आहवाहन किया ।

❖ गत वर्ष सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रो के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, उ प्र शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं SPs हेतु एक विस्तृत SOP जारी की गई थी। बैंको से आहवाहन किया कि ऐसे आवेदन जो विभिन्न न्यायालयों मे लंबित है, की सूची संस्थागत वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सदन को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया:

❖ प्रदेश में कार्यरत शाखाओ की मैपिंग ग्रामों से किए जाने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धको को निर्देशित किया जाये।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक)

❖ पी एम किसान के लाभार्थियो की ग्रामवार सूचना शाखाओं को उपलब्ध कराई जायी ताकि के.सी.सी. एवं पी एम किसान लाभार्थियो की सूचना का मिलान हो सके।

❖ ऐसे जनपद जिनके District Credit Plan & PLP में 60% से 65% तक की dovetailing है, के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं DDM की एक बैठक नाबार्ड द्वारा कराई जानी है जिसमे अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा DCP एवं PLP में gap के कारणो से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

❖ Agriculture Infrastructure Fund Scheme के अंतर्गत प्रगति समीक्षा जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही योजनान्तर्गत अधिक से अधिक ऋण प्रदान किए जाये।

(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं एस.एल.बी.सी.)

❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा प्रीमियम डेबिट कर लिया गया है परंतु इंश्योरेंस कंपनी को remit नही किया गया। बैंको से आहवाहन किया कि डेबिट प्रीमियम को शीघ्र इंश्योरेंस कंपनी को remit किया जाये ताकि किसानो को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ नाबार्ड द्वारा ऋण जमानुपात को बढ़ाने हेतु विस्तृत विश्लेषण कर एक मैट्रिक्स तैयार किया गया जिसमे जनपदवार Credit, Deposit, Advance & Deposit per capita, Deposit & Advances per Sq. km etc पैरामीटर शामिल है। संबंन्धित डाटा वित्त विभाग, उ प्र शासन के साथ साझा किया गया है। अग्रणी बैंको से अनुरोध किया कि अग्रणी जिला प्रबन्धको को उक्त डाटा DDMs से प्राप्त कर जनपदस्तरीय/ ब्लाकस्तरीय बैठको मे विस्तृत समीक्षा करने हेतु निर्देशित करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक)

❖ भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित लक्ष्यो को प्राप्त किए जाने हेतु सभी बैंकों द्वारा आवश्यक प्रयास किए जाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

❖ नाबार्ड द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदो के लिए लगभग 250 फसलों के स्केल ऑफ फाइनेंस का अध्ययन किया गया जिसे शीघ्र ही ACS, Finance द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। बैंको से आहवाहन किया कि अपने अग्रणी जिला प्रबन्धको को निर्देशित करें कि नवंबर माह मे DLTC बैठक के दौरान नाबार्ड द्वारा तैयार स्केल ऑफ फाइनेंस को सभी जनपदों की विशिष्ट फसल के स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ युक्तिसंगत किए जाये।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक)

❖ नाबार्ड द्वारा पी एम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आ रही समस्यायों के निवारण हेतु बैंको एवं वेंडर्स की बैठको का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमती सुमिता सिंह, निदेशक, कृषि सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गत 5 वर्षो के अपेक्षा इस वर्ष खरीफ 2025 सीजन में बैंको द्वारा सर्वाधिक किसानो की फसलों का बीमा किया गया है किन्तु अभी भी काफी अधिक संख्या में पत्र किसान इस योजना में कवर नहीं हुए है। उन्होने बताया कि माननीय कृषि मंत्री द्वारा फ़सली, गन्ना, मत्स्य एवं पशुपालन कृषको को प्रदान किए गए के सी सी की बैंकवार सूचना चाही है ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले कृषको की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। उन्होने बैंको से आहवाहन किया कि खरीफ 2025 की भांति अक्तूबर माह से शुरू होने वाले रबी फसल हेतु भी सभी पात्र कृषको का बीमा कर योजना का लाभ प्रदान करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

*गत एस.एल.बी.सी. की बैठक के दौरान **अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओ एवं उत्तर प्रदेश की विभिन्न पालिसियों को संकलित कर एस.एल.बी.सी., उ. प्र. विभाग द्वारा एक पुस्तिका तैयार की गई जिसका विमोचन बैठक में मौजूद गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया।*

पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति :

- ✓ सर्वप्रथम गत एसएलबीसी की बैठक के दौरान उभरे कार्यवाही बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की गई एवं शीघ्र निरस्तारण हेतु संबन्धित विभागो से अनुरोध किया गया।
- ✓ बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण संकेतको यथा जमा, अग्रिम, ऋण जमानुपात, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं एमएसएमई के अंतर्गत अग्रिम इत्यादि से अवगत कराया गया।
- ✓ **अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने बताया** कि गत वर्षो में आर सी मामलो की संख्या एवं धनराशि मे काफी वृद्धि हुई है जिनमे आरसी जारी कर या लोक अदालत मे निस्तारण की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।
- ✓ **राजस्व परिषद के प्रतिनिधि** ने बैंको से अनुरोध किया कि आर सी पोर्टल पर आवश्यक अपडेशन किए जाये यथा खाता संख्या के स्थान पर मोबाइल नंबर अंकित होना, OTS या अन्य माध्यमों से बैंको मे खाताधारक द्वारा धनराशि जमा किया जाना इत्यादि की सूचना पोर्टल पर अपडेट किये जाने हेतु सभी शाखाओं को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।
- ✓ **अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने निर्देशित किया कि** ऐसे जनपद जिनका ऋण-जमा अनुपात 50% से कम है, में अग्रणी जिला प्रबन्धक संबन्धित जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन में रणनीति तैयार कर नियमित बैठकों के माध्यम से उसकी समीक्षा करें। बैंकों और अग्रणी जिला प्रबन्धको को गत पाँच वर्षों के जमा और अग्रिम आँकड़ों की निगरानी करनी चाहिए और तदनुसार कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ उक्त कार्ययोजना की प्रगति से एसएलबीसी की उपसमिति बैठक के संयोजक बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) को तिमाही आधार पर अवगत करवाया जाए व इसकी समीक्षा उपसमिति बैठक में नियमित रुप से की जाए।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं उपसमिति संयोजक बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

- ✓ बैंकों से अनुरोध किया कि केवाईसी अद्यतनीकरण का CBS Data सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको के साथ साझा करें, ताकि जनसुरक्षा पोर्टल पर वास्तविक उपलब्धि परिलक्षित हो सके।
- ✓ पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत संशोधित दिशा निर्देशों से समस्त बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अवगत कराया गया। योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। सूडा विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा लोक कल्याण मेला (17.09.2025 से 02.10.2025 तक) का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 60,000 नए स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। बैंको से अनुरोध किया कि योजना से संबन्धित संशोधित दिशा निर्देशों हेतु प्रधान कार्यालय स्तर से परिपत्र प्राप्त कर सभी शाखाओं को सूचित करते हुए अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ पहुंचाने मे सहयोग प्रदान करे। योजना के अंतर्गत वितरित एवं बंद किए गए ऋण खातो की सूचना Udyami Mitra Portal पर अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
- ✓ Unclaimed Deposit & DEAF Accounts के settlement हेतु बैंको से आहवाहन किया कि Unclaimed Deposit की पहचान कर ऐसे खातो की जनपदवार सूचना 25.09.2025 तक एसएलबीसी को भेजना सुनिश्चित करे ताकि अक्तूबर माह मे लगने वाले कैंपो मे अधिक से अधिक खातो को settle किया जा सके।
- ✓ वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 New Unbanked Villages की सूची प्रेषित की गई जिन्हे बैंको को शाखा खोलने हेतु आवंटित किया जा चुका है। ग्राम किलौहा, महोबा (केनरा बैंक) मे 22.10.2025 को शाखा खोली जा चुकी है। ग्राम रानाहोर, सोनभद्र (इंडियन ओवरसीज बैंक) मे 31.10.2025 तक शाखा खोली जानी है। ग्राम मड़ैया, चित्रकूट (भारतीय स्टेट बैंक) मे शाखा परिसर हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है। ऊंचाडीह, चित्रकूट (बैंक ऑफ बड़ौदा) हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है। अकथौहा, महोबा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) मे शाखा खोलने हेतु 3 बार टेंडर दिया जा चुका है। उक्त केंद्र पर शीघ्र शाखा खोलने हेतु संबन्धित बैंक से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: संबन्धित बैंक)

✓ **निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग** ने बैंको से आहवाहन किया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले खातो में PMJDY रूपे कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें ताकि लाभार्थी को रू 2 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त हो सके।

✓ बैठक में चर्चा के दौरान, नोडल एजेंसी - केवीआईसी से पी.एम.ई.जी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्राप्त लक्ष्यो को अनुमोदित किया गया जो कि निम्नवत है :

वर्तमान पीएमईजीपी इकाईयों हेतु लक्ष्य			पीएमईजीपी इकाईयों के अपग्रेडेशन के लिये द्वितीय लोन हेतु लक्ष्य		
इकाई	मार्जिन मनी (लाख में)	रोजगार	इकाई	मार्जिन मनी (लाख में)	रोजगार
6206	22977.47	68266	65	351.90	715

✓ **सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि** ने AIF योजना के अंतर्गत वितरित किए गए ऋण की सूचना पोर्टल पर अंकित किए जाने हेतु बैंको से अनुरोध किया ताकि लाभार्थी को भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले Interest Subvention का लाभ प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान योजना के अंतर्गत प्रगति संतोषजनक नही है। बैंको से आहवाहन किया कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे साथ ही ऐसे खाते जिसमे ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, में भौतिक सत्यापन के रूप में Geo Tagging कराना भी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ **यू.पी.एस.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि** द्वारा अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूह – बैंक लिंकेज की समीक्षा प्रत्येक माह CM Dashboard के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। SHG Bank Linkage का डाटा बैंको द्वारा प्रत्येक माह की 15 से 20 तारीख तक पोर्टल पर अपडेट किया जाता है जिससे जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की रैंकिंग प्रभावित होती है। बैंको से अनुरोध किया कि SHG Bank Linkage का डाटा प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख तक पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें। बैंक खातो में केवाईसी अद्यतन किए जाने हेतु बी सी सखियो के साथ साथ बैंक सखियो को भी शामिल किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, एसएलबीसी ने प्रदेश मे बैंक ऑफ बड़ौदा के निष्क्रिय बी सी सखियो (2,500) को बदलने अथवा सक्रिय किए जाने हेतु यू.पी.एस.आर.एल.एम. विभाग से आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: यू.पी.एस.आर.एल.एम. विभाग)

✓ **एम.एस.एम.ई. विभाग के प्रतिनिधि** ने बैंको से CM Yuva योजना के अंतर्गत लंबित 10,630 आवेदन पत्रों में मार्जिन मनी क्लेम किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

✓ सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा CM Yuva, PMFME, PM Surya Ghar, PM Vishwakarma, AIF, ODOP, MYSY इत्यादि में अधिक से अधिक ऋण वितरण किए जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ,लखनऊ

SLBC Jun' 2025 Quarter Ended Meeting 24.09.2025

Participation Sheet

S.no.	Name of Participant	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
1.	Arvind Misra I.P.S.	S.P	EOW, Lucknow (Economic Offences Wing)	9889133333	arvind.misra777@gmail.com	[signature]
2.	Inderjit Singh	Director UPNEDA		9878955674		[signature]
3.	Pankaj Kumar	RD	RBI	9930676708	pankajkumar@rbi.org.in	[signature]
4.	Pankaj Kumar	CGM	Nabard	9833552433	lucknow@nabard.org	[signature]
5.	Shailendra Ku Luthra	GM, SLBC				
6.	Sonali Das	GM	RB	9836107580	sonalidas@rbi.org.in	[signature]
7.	Rajiv Kumar	GM	SIDBI	9711441998	rajivkr@sidbi.in	[signature]
8.	Dr. Nandini Ghose	GM	NABARD	9004317048	nandini.ghose@nabard.org	[signature]
9.	Yadav S. Thakur	Chairman	VBGB.	7506262164	yadav.thakur@bob.co.in	[signature]
10.	Mithilesh Kumar	GM & ZH	BoB, Varanasi Zone	7506964044	mithilesh.kumar@bankofbaroda.com	[signature]
11.	Nidhi Kumar.	DGM	SLBC.	7565005403	slbc.up@bankofbaroda.co.in.	[signature]
12.	Sudhir K. Gupta	CGM	INDIAN BANK	9909922454	sudhir.gupta@indianbank.co.in	[signature]
13.	Kaushalendra Kumar	GM, NW3	SBI	9004961122	gmnw3.lholuc@sbi.co.in	[signature]
14.	Vibhash Kumar	DGM	SBI	8349160740	dgmabu.lholu -	[signature]
15.	[illegible]	GM.	P.N.B	9810509415	[illegible]@pnb.co.in	[signature]
16.	AJIT KUMAR MISHRA	GM	CANARA BANK	8570023669	ajitmishra@canarabank.com	[signature]
17.	A.K. Khanna	ZH	Central Bank of India	8303713848	zmluckzo@centralbank.co.in	[signature]
18.	P.K. Awasthi	D.G.M.	Union Bank of India	7888045921	dyzh.lucknow@unionbank	[signature]
19.	SHRI CHAND	DGM	Bank of India	9868870313	fgmo.lucknow@bankofindia.co.in	[signature]
20.	Vikas Verma	DGM	Indian Overseas Bank	9619126526	0814om@iob.in	[signature]

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
21.	Amit Goyal	Zonal Manager	Bank of Maharashtra	9893003610	zmlucknow@mahabank.co.in	[signature]
22.	A N Singh	ZM	P&SB	9917246207	zmlucknow@psb.co.in	[signature]
23.	Manoj Kumar	Zonal Head	IDBI	7622618804	Kumar.manoj@idbi.co.in	[signature]
24.	SACHIN KUMAR SRIVASTAVA	RH Govt Schemes	HDFC Bank	9359123678	SACHINKUMAR SRIVASTAVA@HDFCBANK.COM	[signature]
25.	Pawan Pant	Vice President	AXIS Bank	9044445841	pawan.pant@axisbank.com	[signature]
26.	Satyajit Roy	Regional Head AGM	ICICI Bank	7388600334	satyajit.roy@icicibank.com	[signature]
27.	Kanchan Chinnadana	Chief Manager	ICICI Bank	8853989342	kanchan.chinnadana@icicibank.com	[signature]
28.	Utsav Raj	Manager	Canara Bank	8181077487	afpscolucknow@canarabank.com	[signature]
29.	Divyanshu Tripathi	Manager	Canara Bank	7706991580	divyanshu5@canarabank.com	[signature]
30.	Khyati Srivastava	AVP	Bandhan Bank	8874096928	CH.LUCKNOW@BANDHANBANK.COM KHYATI	[signature]
31.	Sudhir Singh	Senior Manager	Nainital Bank	7055101600	ashiana@nainitalbank.co.in	[signature]
32.	Avinash Dwivedi	DGM	IDBI Bank Ltd	8891582630	avinash.dwivedi@idbi.co.in	[signature]
33.	Amit Suyash	Sr. Manager	FINO PAYMENTS BANK	6391486257	AMIT.SUYASH@FINOBANK.COM	[signature]
34.	Shudhanshu Shukla	Sr. Manager	Punjab & Sind Bank	991550939	zolucknow@psb.co.in	[signature]
35.	Aishawary Gupta	Manager	Indian Overseas Bank	9795443845	0814pcdagri@iob.in	[signature]
36.	Praveen Yadav	Sr. Manager	Bank of Maharashtra	7355621268	creagr_luc@mahabank.co.in	[signature]
37.	Gaurav Agrahari	Manager	Equitas SFB.	8400020997	gaurav.agrahari@equitasbank.com	[signature]
38.	SAURABH KHARE	Manager	CSB.	7774057195	saurabhkhare@csb.co.in	[signature]
39.	Sanjeev Kr Singh	Sr. Manager	BOI	7017654085	fgmo.lucknow@bankofindia.co.in	[signature]
40.	Bharat Tiwari	Chief Manager	UPGB	9770349636	advances.ho@barodaupgb.co.in	[signature]

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
41.	सुमिता सिंह	निदेशक कृ० सा एवं प्रसार	कृषि	6307104985	agsiddd.up@gmail.com	S. Singh
42.	Prachi Mishra	State Project Manager	UPSRLM	9001708908	mdsrlmup9@gmail.com	Prachi
43.	Monica Verma	ASD (SUDA)	SUDA	7844829712	—	[illegible]
44.	Prashant Mishra	Asstt Direc	KVIC	7753975041	dolucknow.kvic@gov.in	[illegible]
45.	Mahendra Pratap	Dy CEO	U.P.K.V.I.B. Lko	7408410723	ceoupkvib@gmail.com	[illegible]
46.	UTTAM PRAKASH	DIRECTOR	NATIONAL COMMISSION FOR SC	9560252422	dir_ncsc@nic.in	[illegible]
47.	Rashmendra Kumar Saxena	State Director RSETI	MORD	7225055262	sdrlucknow.saxena@gmail.com	[illegible]
48.	Rajesh Kr Yadav	SP Cyber Crime U.P.	POLICE	9454400581	sp-cyber.lu@up.gov.in	[illegible]
49.	Archana Roy	Add. dis. co. officer	COOP/AIF	9792645104	aif.coop2021@gmail.com	ARoy
50.	मोनिका मल्होत्रा	उप महाप्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	9810515354	monica.malhotra@nhb.org.in	मोनिका मल्होत्रा 24/09/2025
51.	जे.बी. यादव	अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त	राजस्व परिषद	9634110008		[illegible]
52.	Irshad Ah. Wani	Sr. Manager	J&K Bank Ltd	7006000721	irshad.a.wani@jkbank...	[illegible]
53.	Suman Kumar	State head	Karnataka Bank	9839222575	lucknow@ktkbank.com	Suman Kumar
54.	Brijesh Kr. Gautam	SP Crime	Police	8810822028	—	[illegible]
55.	Jagannath tiwari	Review officer	BOR	8874644222	—	[illegible]
56.	SHISHIR SHUKLA	CM	YES BANK	9837122530	SHISHIR.SHUKLA@YES BANK.IN	[illegible]
57.	Apoorv Kapoor	PM	Yes Bank	9794999220	apoorv.kapoor@yesbank.in	[illegible]
58.	YUSUF KHALIL	ZSH-Liability	UTKARSH SMALL FINANCE BANK	8874223666	yusuf.khalil@utkarsh.bank	[illegible]
59.	Ruchi Upadhyay	V.P.	Kotak Mahindra Bank	7060222107	ruchi.upadhyay@kotak.com	Ruchi Upadhyay
60.	Abhishek Kumar	AVP	Federal Bank	7488138107	lkw@federalbank.co.in	[illegible]

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
61.	Shashank Sengar	Nodal Officer	NPCI	9654196932	shashank.sengar@npci.org.in	[signature]
62.	PRABHASH TRIVEDI	AVP	PAYTM PAYMENTS BANK LTD	7785926117	prabhash.trivedi@paytmbank.com	[signature]
63.	Sujit K. Rajbhar	FIDO	Horticulture & Food processing	7007160565	amfpmup@gmail.com	[signature]
64.	VIPIN VERMA	Dy. Director	UIDAI, RO Lucknow	7007735132	dd3-rolko@uidai.net.in	[signature]
65.	Aiman Parvez	AM	UIDAI RO LUCKNOW	9599925140	am1-rolko@uidai.net.in	[signature]
66.	Harshita Goyal	State Mission Manager	SUDA	9161472224	harshitajuly@gmail.com	[signature]
67.	Uma Shankar Singh	Joint Director Agriculture Stat.	Agriculture	8795042156	—	[signature]
68.	S. D. Dubey	Advisor	UPNEDA	7607262706	shyamdubey05@gmail.com	[signature]
69.	Upkari Nath	Advisor	UPNEDA.	7905636818	upkorinath@gmail.com	[signature]
70.	Bablesh Kumar	ARO	DIF-UP. Govt.	9452034500	—	[signature]
71.	Jai Govind Prasad	A.D.	DIF. UP. Govt.	9807880822	—	[signature]
72.	Alok Maurya	A.D.	DIF. UP Govt.	8700261618	—	[signature]
73.	Sameer	Spl. Sec.	Finance	9415607120		[signature]
74.	Inderjit Singh	Director	UPNEDA	9878915674		[signature]
75.	KC Prasad	Asst (V.I)	KVIC	9814480450	—	[signature]
76.	SUNIL KUMAR	R.M.	Shivalik Small Finance Bank	6392884355	—	[signature]
77.	AMRISH KUMAR SINGH	Regional Nodal Officer	AU Small Finance Bank Ltd.	9116658179	amrish.singh@aubank.in	[signature]
78.	ABHISHEK KUMAR	Consultant-FI UPSRLM	UPSRLM	9711865393	abhi.kumar.cns@microsave.net	[signature]
79.	[illegible]	[illegible]	HCPC	7734967774	gireesh.kumar.rathore88@gov.in	[signature]
80.	Rishabh Tomar	IT Expert	AIF, Cooperative Dept.	9818500832	aif.coop2021@gmail.com	[signature]

S.no.	Name of Participants	Designation	Name of Organization/ Deptt.	Contact No.	Email id	Signature
81.	Ajay Kumar	AGM.	SBI	9452183363	agmeb.lw.luc@sbi.co.in	[signature]
82.	ANKKIT GUPTA	SM	INDIAN BANK	7985180873	FGMO.LUCKNOW@INDIANBANK.CO.IN	[signature]
83.	Ankur Khandelwal	SM	IPPB	7905130059	uttarpradeshcircle@ippbonline.in	[signature]
84.	Abhishek Tripathi	SM	IPPB	9587412777	abhishek.t@ippbonline.in	[signature]
85.	Lakshmi Singh Upadhyay	ACI	District Industries Promotion & Enterpreneurship Development Centre (Formerly DIC), Lucknow.	9454602806/ 9161300528	lakshmi.02806@up.gov.in	[signature]
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100						